

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठारसीन अधिकारी- चौद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 129/2018

सुदेश कुमारी पुत्री श्रीमति तारादेवी पुत्री भौड़ू उर्फ बैनथू जाति जट निवासी महाल भदवाड़ा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) जरिये मुख्याराम जसवीर सिंह पुत्री कुलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एलएनपी (चक महाराजका) तहसील व जिला श्रीगंगानगर



बनाम

1. सुखवीर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एसकेएम ए तहसील धडसाना वर्तमान तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
2. चुहडीदेवी पुत्री भौड़ू उर्फ बैनथू निवासी घोली डाक लौहारा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
3. चहलो देवी पुत्री भौड़ू उर्फ बैनथू निवासी घोली डाक लौहारा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भूअ. रावला जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिथत:-

1. अधिवक्ता अपीलांत श्री तिलक राज चुघ
2. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट श्री नरेश चुघ

निर्णय

दिनांक: 01.02.2018

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 5 एसकेएम ए उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ न. 1 वर्तमान तहसील रावला का मुरबा न. 147/21 के किला न. 1 ता 25 के 25 बीघा कृषि भूमि अपीलांत के नाना भौड़ू उर्फ बैनथू पुत्र श्री नन्दू को पौंगबांध विस्थापितों में पुख्ता आवंटन हुई थी। बैनथू का देहान्त दिनांक 11.10.1980 को हो गया। बैनथू के तीन पुत्रीयां कमशः चुहडी देवी, चहलो देवी व तारा देवी थी। अपीलांत तारादेवी की एक मात्र विधिक वारिस है। आवंटी बैनथू के मृत्यु पश्चात उक्त कृषि भूमि अपीलांत व रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 को विरास्तन प्राप्त हुई है उक्त कृषि भूमि में अपीलांत का हक व अधिकार निहित है। लेकिन रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने तथाकथित वसीयत तैयार कर ली और उक्त वसीयत के आधार पर उपनिवेशन तहसील इ.ग.न.प. छतरगढ़ न. 1 से अपीलाधीन भूमि का इंतकाल संख्या 25 दिनांक 30.11.89 को अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया।
2. अपील संख्या 129/2017 पर दर्ज की गई। व उभय रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांत की तरफ से अधिवक्ता श्री तिलक राज चुघ हाजिर हुए व रेस्पोंडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेश चुघ उपरिथत आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांत ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि भौड़ू उर्फ बैनथू को पौंगबांध विस्थापितों में पुख्ता आवंटन हुई थी। उक्त इंतकाल राजस्थान कार्रकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर स्वीकृत किया गया है। रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने तथाकथित वसीयत अपने पक्ष में बताई है तो तथाकथित वसीयत आवंटी बैनथू की मृत्यु दिनांक 11.10.1980 से पूर्व की प्रतीत है जबकि अपीलाधीन कृषि भूमि तथाकथित वसीयत के समय गैरखातेदारी थी और कानूनन गैरखातेदारी भूमि की वसीयत करने में मूल आवंटी बैनथू सक्षम नहीं था। इस प्रकार गैरखातेदारी कृषि भूमि की वसीयत आरम्भ से ही प्रभावहीन व प्रभावशून्य तथा गैर कानूनी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है व विधिविरुद्ध यह इंतकाल दर्ज किया है। उक्त इंतकाल दर्ज करने से बैनथू के वारिसों को सुना नहीं गया। अतः अपील स्वीकार की जावे व इंतकाल निरस्त कर पुनः जांच कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जावे। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहीर नहीं की।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

हमने पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन, चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रश्नगत इंतकाल के विरुद्ध लगभग 30 वर्ष पश्चात अपील पेश की है। विलम्ब से प्रस्तुत अपील तभी ग्राह्य है जब उसके प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। विलम्ब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। प्रस्तुत अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें विलम्ब का कारण सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय ना होने कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाता है। व इसी आधार पर अपील अपीलांट भी खाजिर की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature) 01-2-18
 (चाँद मल वर्मा)
 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 सुप्रीम कोर्ट